## टेलीफोन संगठनों का बंद किया जाना

†*59. **श्री रमा शंकर कौशिक:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एम॰टी॰एन॰एल॰ और बी॰एस॰एन॰एल॰ सहित सभी सरकारी टेलीफोन संगठनों को बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो ग्रामीण, मध्यम और निम्न-वर्गीय लोगों द्वारा प्रयोग किए जा रहे घरेलू टेलीफोन को महंगा और मोबाइल फोन को सस्ता करने का क्या औचित्य है; और

(ख) क्या सरकार घरेलू फोन की बढ़ी हुई दरें वापस लेने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अरुण शौरी):** (क) जी, नहीं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा 24 जनवरी, 2003 के दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 के 24वें संशोधन के तहत टैरिफ पुनर्संतुलन संबंधी कार्य किए जाने के कारण, फिक्सड टेलीफोनों के लिए टैरिफ घोषित किया गया है। आदेश में उल्लिखित टैरिफ, मानक टैरिफ पैकेज के रूप में हैं। सेवा प्रदाता, अपनी लागत तथा उपभोक्ताओं की उपयोग पद्धति को ध्यान में रखते हुए, वैकल्पिक टैरिफ पैकेज देने के लिए स्वतंत्र हैं। 24वें संशोधन में मोबाइल फोनों के संबंध में बुनियादी टेलीफोनी के टैरिफ में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार प्राधिकरण को मानक टैरिफ निर्धारित करने का विशेष अधिकार प्राप्त है तथा इस समय टैरिफ की समीक्षा करने का उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

## Closing down of Telephone Organisations

†*59. SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to close all Government telephone organisations including MTNL and BSNL, if so, the reasons therefor and if not, the justification for making domestic telephone, being used by rural and middle and lower class people costlier and mobile phones cheaper; and

(b) whether Government are considering to withdraw the increase in

†Original notice of the question was received in Hindi.

rates of domestic phones, if so, the details thereof, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER FOR COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI ARUN SHOURIE): (a) No, Sir. The tariff for fixed telephones announced by TRAI vide 24th Amendment to TTO, 1999 dated 24th January, 2003 is the result of its tariff rebalancing excercise. The tariff specified in the order is in the form of standard tariff package. The service providers are at liberty to offer Alternative Tariff Packages depending upon their cost and usage pattern of subscribers. The 24th Amendment has not proposed any increase in tariff of basic telephony with reference to mobile phones.

(b) No, Sir. As per the TRAI Act, TRAI has the exclusive jurisdiction for fixing standard tariffs and there is no proposal with them to review the tariff at this stage.

**डा० कुमकुम राय:** सभापति महोदय, व्यापार के सामान्य सिद्धांत के आधार पर सरकार से व्यवसाय के लिए समान धरातल उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुरोध किया जाता है। सामान्यता इसका अर्थ यह होता है कि किसी को भी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से ऐसी कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध न कराई जाए, जिससे अन्य के मुकाबले उसे विशेष लाभ मिल जाए और अन्य कंपनियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा में हानि उठानी पड़े। किन्तु, इसका खंडन करते हुए ट्राई ने इस बार जो अपनी नई दर-व्यवस्था घोषित की है उसमें यह बड़ी विचित्र स्थिति सामने आई है कि सेलुलर आपरेटरों एवं सीमित मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के साथ और अन्य कंपनियों के साथ एक जंग छिड़ी और जिसका खामियाजा भुगता सामान्य आम जनता ने। इसकी गाज सीधे बुनियादी यानि सामान्य टेलीफोन उपयोग करने वाले लोगों पर गिरी। यह जो अन्यायपूर्ण दर निर्धारित की गई है, इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना है कि ट्राई ने जो अपने तर्क में यह कहा है कि स्थानीय कॉलों को सबसिडी मिलती रही थी इसलिए स्थानीय कॉल सस्ती थीं और अब सबसिडी समाप्त कर दी गई है इसलिए यह स्थानीय कॉल महंगी कर दी गई हैं, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस प्रकार के कोई आपके पास डाटा हैं, जिसके आधार पर आप यह तर्क साबित कर सकें कि सबसिडी के माध्यम से कॉल सस्ती और महंगी करने की बात होती है? मैं चाहूंगी कि आप इसे उस डाटा बेस के हिसाब से प्रमाणित करें।

SHRI ARUN SHOURIE: The power to fix tariffs is given by Parliament under the TRAI Act to the Regulator. The Government cannot interfere in that. The TRAI has been fixing rates since 1999 और फिर जो काम्प्लैक्स आर्डर

है, सर, मुझे पांच घंटे लगे उसको समझने के लिए और यह 23 पेज का आर्डर है, जिसमें बहुत सी क्लासिस और सब-क्लासिस वगैरह हैं।

**श्री सभापति:** इतना मुश्किल विषय है कि आपको पांच घंटे लगाने पड़े?

**श्री अरुण शौरी:** हां, सर लगाने पड़े। उसमें एक समझने की बात है because of the TRAI's efforts in this regard in the last three years these STD rates have come down by 62 per cent. उसमें उस फायदे को भी देखें। ऑनरेबल मैम्बर साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ऐक्सैस डेफिसिट चार्ज होता है for meeting a subsidy which is paid by charging for long distance calls and to subsidise other services, for instance free calls. There is a way of subsidising that. किसी ने तो पैसे देने हैं। अब चूंकि कंपीटीशन आया है सेलुलर फोन से Therefore, the basic service providers such as MTNL, BSNL, TATAs or Reliance, also reduce their rates. Therefore, the way of giving subsidy has become compressed. I had a discussion with BSNL and MTNL that they should try flexible packages so that subsidies or something can be continued in some other form and we can have expansion in rural areas and so on. मगर, सर, यह पावर ट्राई की है। मैडम, एक और प्वांइट, जो आपने अन्याय की बात कही, उसकी एक ही रैमिडी है कि ट्राई के इस आर्डर के अगेंस्ट एक ऐपिलेट अथारिटी है "टीडीसैट" और जो सेलुलर ऑपरेटर्स वगैरह हैं, उन्होंने "टीडीसैट" में इन चीजों पर भी केस फाइल किया है। बीएसएनएल केस फाइल नहीं कर रही, बीएसएनएल यह स्टडी कर रही है कि हम कैसे फ्लेक्सिबल पैकेज दें जिससे कि सुविधा भी मिले और किसी पर ज्यादा बात भी न आए।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, it is an important subject. ...(*Interruptions*)... We should discuss it exhaustively ...(*Interruptions*)..

**डा॰ कुमकुम राय:** सर, बीएसएनएल की जो बातें मंत्री महोदय ने कही हैं, इससे तो निष्कर्ष यह निकला कि घरेलू फोन महंगे हो गए, मोबाइल सस्ते हो गए। इससे पहले तमाम सेलुलर आपरेटर्स और पूर्व मंत्री जी के बीच में जो सुलह-सफाई हुई थी, वह पूरा दिखावा दिखाई पड़ता है और इससे जो बुनियादी सेवा मुहैया.....

**श्री सभापति:** आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। मंत्री जी पांच घंटे की स्टडी करके आए हैं, तुरंत जवाब मिल जाएगा।

**डा॰ कुमकुम राय:** सर, मेरा कहना है कि इन्होंने माननीय पूर्व मंत्री महोदय, श्री प्रमोद महाजन जी से बात कर ली होती तो पता चल जाता कि वह किस तरह दक्षिण अफ्रीका का दौरा छोड़कर आए और कुछ घंटों में ही उन्होंने सारे मामले सुलझा दिए थे। मेरा यह मानना है कि 13 से 15 लाख लोग हर

साल बीएसएनएल के फोन लौट रहे हैं। तो इनकी यह मंशा साफ है कि इससे बेसिक फोन को घाटा होगा, उनको क्षति होगी और इस पर मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं।

**श्री अरुण शौरी:** सर, मेरे आने से पहले जो ट्राई ने कुछ आर्डर दिया, उसके बारे में मेरे उपर आरोप लगाया गया है, यह तो अजीब बात है।

**श्री सभापति:** यह आरोप नहीं है।

**डा॰ कुमकुम राय:** सर, मैं कहना चाहती हूं कि मंत्री कोई भी रहे हों, लेकिन सरकार की कार्रवाई तो निरंतरता में चलती है। यह इनके मंत्रालय ने किया। एक अरब की आबादी वाले इस हिन्दुस्तान में ...(**व्यवधान**)...

**श्री संजय निरूपम:** अगर बात जनता के हितों के खिलाफ है ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापति:** संजय जी, एक महिला सदस्य बोल रही हैं, आप उनको इंटरप्ट कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... वे खुद बहुत होशियार हैं।

**डा॰ कुमकुम राय:** माननीय मंत्री महोदय एक अरब के इस मुल्क में टेली डेंसिटी बढ़ाने की दुहाई देते हैं, उस आधार पर 13-15 लाख लोग हर साल बीएसएनएल के फोन वापिस कर रहे हैं, इस बारे में मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्री सभापति:** वह बाद में कर लीजिएगा, कभी कर लीजिएगा।

**डा॰ कुमकुम राय:** इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्रमोद जी रहें या शौरी जी इस पद पर नहीं रहेंगे कोई दूसरे आ जाएंगे, इससे जनता को क्या फर्क पड़ता है।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** श्रीमन्, विडम्बना तो यह है ...(**व्यवधान**)...

**डा॰ कुमकुम राय:** सर, मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दिया जाय। सर, मंत्री महोदय से कहा जाए।

**श्री संतोष बागड़ोदिया:** सर, मंत्री महोदय इनके दूसरे सप्लिमेंट्री क्वेश्चन का जवाब तो दें।

SHRI KAPIL SIBAL: There should be a discussion for one hour. ...(*Interruptions*).. This is an important subject.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: It needs an elaborate discussion. ...(*Interruptions*)..

**श्री अरुण शौरी:** सर, अगर आप कहें तो मैं जवाब दे देता हूं।

**श्री सभापति:** दे दीजिए। ..(**व्यवधान**)..

SHRI ARUN SHOURIE: What should I do? ....(*Interruptions*).. मैं जवाब दे सकता हूं लेकिन अगर चेयरमैन साहब किसी और को बोलने के लिए कहें तो मैं क्या कर सकता हूं। Firstly that is not the case. In the case of the rental orders of the TRAI....(*Interruptions*)..

**डा० कुमकुम राय:** सर, मैंने हिन्दी में प्रश्न किया है।

**श्री अरुण शौरी:** सर, रूरल एरिया है, वहां जो फोन का रेंटल है, अगर लोकल ऐक्सचेंज की केपिसिटी है, मैं अगर सारा आर्डर पढ़ूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह नहीं है कि कॉमन मैन इसको छोड़ता जा रहा है। आप कहें तो मैं वह डिटेल पढ़ देता हूं।

**श्री नीलोत्पल बसु:** वह है न स्टेटमेंट में।

**डा० कुमकुम राय:** सर, मैंने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर नहीं दिया गया। हमने एक लाइन में मंत्री जी से उत्तर मांगा है।

**श्री सभापति:** मंत्री जी, जो प्रश्न किया गया है वह गंभीर है।

**श्री अरुण शौरी:** बिल्कुल। आप जब भी चाहें, इस पर पूरी डिस्कशन होनी चाहिए। आप जब चाहें।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** श्रीमन्, विडम्बना यह है कि आम लोगों की सरकार का दावा करने वाली इस सरकार के समय में सेलफोन जो केवल एक करोड़ से बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके किराये तो घटते चले जा रहे हैं, उनकी इनकमिंग कॉल फ्री होती चली जा रही हैं और श्रीमन्, जो बुनियादी टेलीफोन हैं उनकी कीमतें, उनका किराया बढ़ता चला जा रहा है। श्रीमन्, अब इसकी पल्स दर 180 सेकेंड के बजाए 120 सेकेंड होगी। मोबाइल, "विल" के लिए भी इनकमिंग नि:शुल्क हो गई है। नगरों में निजी कॉल्स 60 के बजाए 30, ग्रामीण क्षेत्रों में 75 के बजाए 50 फ्री हो गई हैं।

**श्री सभापति:** यह तो जानकारी है, आप सीधा प्रश्न पूछ लीजिए।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** श्रीमन्, प्रश्न यहां यह है कि अगर सब कुछ यह ट्राई को ही करना है तो यह सरकार क्यों बनी बैठी है। अगर कोई भी संगठन जो सरकार द्वारा बनाया गया है तथा वह अन्याय करता है, भेदभाव करता है और आम लोगों के कष्टों को बढ़ाता है तो क्या सरकार का दायित्व यह है कि वह कान में तेल डाल कर बैठ जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि .......(**व्यवधान**)

**श्री अरुण शौरी:** ऐसे शब्द प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सरकार ने नहीं किया है, यह आपने किया है, पार्लियामेंट ने किया है।

**श्री सभापति:** किसी ने किया हो।

**श्री अरुण शौरी:** पार्लियामेंट ने एक्सक्लूसिव पॉवर दी हैं टेलीकॉम रेग्यूलेटरी को। दूसरे, पार्लियामेंट ने पॉवर दी है गवर्नमेंट को किसी चीज पर डायरेक्शन देने के लिए Please, do not come in those directions...(*Interruptions*)...आप एक्ट अमेंड कीजए।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** फिर आप क्या करेंगे?

SHRI ARUN SHOURIE: I firmly believe that nobody should interfere in the affairs of the regulator...(*Interruptions*)...You are setting up regulatory regimes, and then you want us to intervene in their affairs! ...(*Interruptions*)...Yesterday, Dr. Manmohan Singh was saying, "Why the Government is interfering after disinvestment?" ...(*Interruptions*)...

**श्री दीपांकर मुखर्जी:** आप इधर आ जाइए हम उधर चले जाते हैं।........(**व्यवधान**)

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, let there be a detailed discussion on this...(*Interruptions*)...

**श्री सभापति:** कोई रिकार्ड नहीं किया जाएगा, जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई संगठन सरकार के द्वारा बनाया गया हो, पार्लियामेंट के जरिए बनाया गया हो और वह अगर अन्याय करता है और आम लोगों के कष्टों को बढ़ाता है तो क्या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस मामले में जो बुनियादी टेलीफोन है जिसे आम जनता इस्तेमाल करती है उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के निराकरण के लिए क्या कोई उपाय सरकार करेगी?

**श्री अरुण शौरी:** पहली चीज जिसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बी॰एस॰एन॰एल॰ और एम॰टी॰एन॰एल॰ से मैंने डिसकसंस किए हैं, क्योंकि जो ट्राई ने कहा है वह मिनिमम रेट नहीं है, वह स्पेसिफिक रेट नहीं है, उन्होंने सीलिंग प्रेस्क्राइब की है। उसके अन्दर बी॰एस॰एन॰एल॰ और एम॰टी॰एन॰एल॰ क्या कर सकते हैं जिससे आम आदमी को कष्ट न पड़े। दूसरी चीज यह है कि इसी एक्ट में जैसे कौशिक जी ने कहा कि क्या रेमेडी है। अगर अन्याय हो तो आपने, पार्लियामेंट ने उसमें एक रेमेडी दी है। रेमेडी यह है कि टीडीसैट में जाएं जो एफेक्टेड हैं। मैंने बी॰एस॰एन॰एल॰ और एम॰टी॰एन॰एल॰ से पूछा कि आप जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इसी का समाधान अपने फलेक्सेबिल पैकेजिज से ढूंढेंगे।

**श्री रमा शंकर कौशिक:** तो क्या सरकार जाएगी?

श्री सभापति: बस, हो गया।

श्री रमा शंकर कौशिक: श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में सरकार जहां अपील कर सकती है वहां अपील करने के लिए जाएगी या आम जनता जाए या करोड़ों की तादाद में जो जनता बुनियादी टेलीफोन इस्तेमाल करती है वह जाए?

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, at the very outset, I appreciate the time Mr. Shourie has given to study the Order. But, at the same time, I think, two other documents are also very relevant for replying to this question. The first one is, the National Telecom Policy, 1999. It lays down increasing the teledensity as one of the primary objectives of the National Telecom Policy. Now, the teledensity has an inverse function of a ratio of a minimum access fee to per capita GDP. Sir, clearly, this TRAI Order will result in a situation where the minimum access fee will go up and therefore, the inverse ratio of the minimum access fee to per capita will go up. So, therefore, the teledensity will be adversely affected. Article 16 of the TRAI Act, to which you have made a reference, clearly gives a right to the Government to issue directions to the TRAI in the public interest. Now, it is contrary to the objectives of the National Policy. Therefore, will the Government issue a direction to the TRAI to the effect that this rebalancing will have an adverse effect on the teledensity?

SHRI ARUN SHOURIE: Sir, Section 16 does not say that. It is regarding the procedure and powers of Appellate Tribunal. (*Interruptions*) Rather, section 25 deals with powers of the Central Government to issue directions. The Parliament had said that the Central Government could, from time to time, issue such directions, as it might think necessary, to the Authority in the interest of the sovereignty and integrity of India, security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality. अब इसमें किस तरह से आता है? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जितना आये। ...(व्यवधान)... एक मिनट। ...(व्यवधान)...

श्री अरुण शौरी: आप सुनिए तो सही। ...(व्यवधान)...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, he is distorting...(*Interruptions*)

SHRI ARUN SHOURIE: I am giving you the text of the laws. (*Interruptions*) Your point is good. (*Interruptions*)

SHRI NILOTPAL BASU: The TRAI Act was ...(*Interruptions*).... by the Parliament in the background of the National Telecom Policy. (*Interruptions*)

**श्री सभापति:** मंत्री महोदय, आप एक काम करिए। जिस तरह की प्राब्लम इम्पोज की गई है उसका किस प्रकार से साल्युशन हो सकता है, आप उस पर विचार करिए।

**श्री अरुण शौरी:** सर, यह बहुत अच्छा सुझाव है।

*50. [The questioners Shrimati Ambika Soni and Dr. T. Subbarami Reddy were absent. For answer *vide* pages 53-54 *infra*.]

*51. [The questioners Shri Dasari Narayana Rao was absent. For answer *vide* pages 54-55 *infra*.]

**Beneficiaries of PMRY**

*52. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of AGRO AND RURAL INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is fact that to promote the concept of self employment among the youth, Government have launched a scheme called Prime Minister Rozgar Yojana;

(b) if so, the details of the beneficiaries under the scheme in the last three years, State-wise;

(c) what has been the target fixed for Andhra Pradesh during the said period and what have been the achievements, district-wise; and

(d) what steps Governments are contemplating to make the scheme effective?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI SANGH PRIYA GAUTAM): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

***Statement***

(a) Yes, Sir.

(b) Based on the monitoring reports received from the Reserve Bank of India (RBI), state-wise details of beneficiaries disbursed loans during the last three years i.e. 1999-00, 2000-01 and 2001-02 under the Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) is given in enclosed Statement-I (*See* below).